महत्वपूर्ण और सैन्य मापन में चीन–पाक संबंध

DR. VIJENDER KUMAR
ASSISTANT PROFESSOR
DEPT., OF POLITICAL SCIENCE
SHRI JJT UNIVERSITY, JHUNJHUNU, RAJASTHAN

सार

पाकिस्तान और चीन के संबंध एक–दूसरे के गैर–हस्तक्षेप सिद्धांतों पर आधारित हैं। इन गैर–हस्तक्षेप के उदाहरण पूर्वी पाकिस्तान और शिनजियांग मुद्दे हैं। पाकिस्तान ने 1949 में चीन को मान्यता दी। उसने पूर्वी पाकिस्तानी अलगाववादियों के आधार का समर्थन करने से इनकार कर दिया और पाकिस्तान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन किया। 1962 के चीन–भारत युद्ध ने इन संबंधों को और मजबूत किया (सैयद , 1969)। भारत–पाकिस्तान के इतिहास के दौरान, भारत ने चीन पाकिस्तान के संबंधों पर कटाक्ष किया था। चीन–पाकिस्तान संबंधों का मुकाबला करने के लिए भारत ने अमेरिका को अपना रणनीतिक साझेदार बनाया। दोनों (पाकिस्तान और चीन) राज्यों की विदेश नीति दर्शाती है एक दूसरे के हित। पाकिस्तान में चीन का निवेश पाकिस्तान के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा दे रहा है, जबकि दूसरी ओर दुनिया भर में अपने व्यापार के लिए पाकिस्तान के माध्यम से चीन के लिए एक सुरक्षित और सुगम मार्ग उपलब्ध है (कुमार, 2007)। चीन अपने निर्यात के लिए पाकिस्तान को एक प्रवेश द्वार के रूप में लेता है और निर्माण कर रहा है।

परिचय

जैसे–जैसे चीन के साथ पाकिस्तान के संबंध राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य मोर्चे पर बढ़ रहे हैं, यह बेहतर ढंग से परिभाषित भी हो रहा है। गठबंधन को अधिकारियों द्वारा सम्मान और 'बहुआयामी' सहयोग पर आधारित एक पारस्परिक रूप से लाभप्रद संबंध के रूप में वर्णित किया गया है, और यह अक्सर दो देशों के सुरक्षा क्षेत्रों में अन्य देशों की कथित क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं, अर्थात् संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत द्वारा उचित ठहराया जाता है।

पाकिस्तान में आतंकवाद–रोधी पहलों का समर्थन करने में चीन की रुचि का उद्देश्य शिनजियांग में अपनी आंतरिक स्थिरता के लिए कोई भी खतरा होना और पाकिस्तान में चीनी निवेश और कर्मियों की सुरक्षा को सुरक्षित रखना है। हालाँकि पाकिस्तान रिश्ते के आर्थिक आयाम पर जोर दे रहा है, लेकिन यह उसके लिए रिश्ते का केंद्रीय चालक नहीं है। चीनी निवेश रणनीतिक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जहां राज्य की

भागीदारी महत्वपूर्ण है। चीन पाकिस्तान के निजी क्षेत्र में उसी तरह से निवेश नहीं कर रहा है जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और संयुक्त अरब अमीरात कर रहे हैं।

सामरिक सहयोग को बनाए रखना पाकिस्तान की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य रहा है। इसे और मजबूत किया गया जब 1970 के पाकिस्तान ने चीन के साथ रक्षा, आर्थिक विकास और व्यापार आदि में सहयोग पर विभिन्न प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए, चीन ने अपेक्षाकृत कम कीमतों और उदार शर्तों पर पाकिस्तान को हथियारों की आपूर्ति के सबसे विश्वसनीय स्रोतों में से एक साबित किया। एक निरंतर हथियार आपूर्तिकर्ता के अलावा, बीजिंग ने अनिर्दिष्ट हथियारों और गोला–बारूद के स्थानीय उत्पादन में इस्लामाबाद की मदद की, और अन्य भारी मशीनरी , पश्चिमी ऋणों के विपरीत चीनी सहायता कार्यक्रम अक्सर रक्षा औद्योगिक परियोजनाओं के लिए थे। चीन ने जब भी बुरी तरह से जरूरत पड़ी, पाकिस्तान को आर्थिक और सैन्य सहायता दी और यह आज भी नियमित रूप से जारी है। 1965 के युद्ध के बाद से चीन पाकिस्तान के हथियारों के निर्माण में मदद कर रहा था और 1979 में यह जेनिथ तक पहुंच गया। अफगानिस्तान के सोवियत सैन्य कब्जे ने उनकी दोस्ती को और मजबूत किया।

चीन ने पाकिस्तान के साथ उन्नत तकनीकों को साझा किया और हमेशा हथियारों और तकनीकी विकास के लिए पश्चिम पर अपनी निर्भरता को दूर करने के लिए पर्याप्त प्रयास किया। हथियारों की चीनी सहायता ने पाकिस्तान की आत्मनिर्भरता और हथियारों की क्षमताओं के स्वदेशीकरण की दिशा में काफी हद तक योगदान दिया है। पाकिस्तान की ओर उसकी हथियारों की निर्यात नीतियों में चीन को कभी भी किसी अंतरराष्ट्रीय हथियार नियंत्रण शासन या अंतर्राष्ट्रीय जनमत से विवश नहीं होना पड़ा। चीन के निरंतर सहयोग ने निर्णय लेने वाली संरचनाओं के भीतर पाकिस्तान की सेना के प्रभाव और भूमिका को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है जो पहले से ही सशस्त्र बलों के प्रभुत्व थे। निस्संदेह चीन और पाकिस्तान के बीच इस बहुपक्षीय सहयोग ने पाकिस्तान की सुरक्षा को भारत की सुरक्षा और प्राकृतिक रूप से लुप्त होती सुरक्षा को काफी हद तक मजबूत किया है।

पाकिस्तान को परमाणु और मिसाइल सामग्री और प्रौद्योगिकी हस्तांतरित करने में प्रेरणाएं काफी हद तक शक्ति के क्षेत्रीय संतुलन के बारे में चीनी चिंताओं से उत्पन्न होती हैं और भारत के साथ अपनी प्रतिद्वंद्विता में भागीदारी की रणनीति को आगे बढ़ाने के लिए चीनी प्रयास का हिस्सा है। उदार पैमाने पर पाकिस्तान को युद्ध सामग्री की आपूर्ति करने में, चीन ने निवेदन किया कि उसे सहयोगी के रूप में अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए पाकिस्तान की आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। इस संदर्भ में,

चीन–पाकिस्तान सहयोग के रक्षा, परमाणु और मिसाइल आयाम की जांच करना हमारे उद्देश्यों के लिए महत्वपूर्ण है।

रक्षा सहयोग :–

पिछले 3वीं दशकों के दौरान चीन–पाकिस्तान संबंधों की सबसे महत्वपूर्ण, विवादास्पद और शायद मौलिक विशेषता दोनों राज्यों के बीच एक बहुपक्षीय रक्षा सहयोग रहा है। सत्तर और अस्सी के दशक के दौरान पाकिस्तान लगातार चीनी हथियारों के शीर्ष पांच प्राप्तकर्ताओं में से एक रहा है जब बीजिंग ने राजनीतिक और भू–रणनीतिक कारणों से हथियारों की आपूर्ति की।

पिछले 35 वर्षों में, चीन–पाकिस्तानी रक्षा सहयोग को भारत के साथ लंबे समय से चली आ रही समस्याओं और दोनों देशों द्वारा प्रोत्साहित किया गया है। विशेष रूप से इस्लामाबाद के लिए, सुरक्षा दृष्टि–ए–विज नई दिल्ली की खोज अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए प्रेरित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक रहा है, जिसमें बीजिंग ने स्पष्ट रूप से गॉडफादर की भूमिका निभाई है। अपनी आंतरिक अस्थिरता के संदर्भ में पाकिस्तान का रक्षा प्रयास एक तथ्य है। पाकिस्तान ने अपने सशस्त्र बलों को पैदा करने के लिए मदद लेनी शुरू की और लगभग 1950 के दशक के मध्य तक पैदा हुआ। रक्षा की तलाश में यह पश्चिमी शक्तियों के साथ विभिन्न सैन्य गठबंधनों का एक महत्वपूर्ण सदस्य बन गया था। इन गठबंधनों में केंद्रीय संधि संगठन और दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन शामिल थे। नतीजतन, पाकिस्तान को पश्चिमी आपूर्तिकर्ताओं से हथियारों और उपकरणों का एक नियमित प्रवाह प्राप्त करना शुरू हुआ, जो पाकिस्तान को विशाल कम्युनिस्ट राज्यों – सोवियत संघ और पीपुल्स चाइना के अपने हिस्से में भागीदार बनाना चाहते थे। हालाँकि, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा बार–बार शस्त्रों का त्याग, और स्वदेशीकरण और आत्मनिर्भरता के साथ भारत के प्रयोगों की प्रारंभिक सफलता ने पाकिस्तान को चीन के साथ धकेल दिया। पाकिस्तान ने हथियारों की आपूर्ति के अपने स्रोतों में विविधता लाने और अपने रक्षा उपकरणों के स्वदेशी उत्पादन के प्रयास के तहत चीन के साथ रक्षा संबंध बनाने शुरू कर दिए थे। इस दोस्ती को बाद में 1962 और 1965 के चीन–भारतीय और भारत–पाकिस्तान युद्धों ने मजबूत किया, जिसके बाद बीजिंग ने पाकिस्तान को भारत के साथ निपटने में अपने प्रमुख सहयोगी के रूप में कल्पना करना शुरू कर दिया।

उत्पत्ति :–

सितंबर 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू होने पर पाकिस्तान को अमेरिकी सैन्य सहायता बंद हो गई। 08 सितंबर, 1965 को अमेरिकी हथियार बंद हो गए, जिसके द्वारा वाशिंगटन ने भारत

और पाकिस्तान दोनों को सभी सैन्य आपूर्ति रोक दी, क्योंकि पाकिस्तान पक्षपाती था, क्योंकि यह पाकिस्तानी सेना थी। पूरी तरह से अमेरिकी उपकरणों पर निर्भर थे। हकीकत यह है कि अमेरिकी भरपाई के अभाव में पाकिस्तानी फौजों को हफ्तों के भीतर रक्षाहीन बना दिया जाता, हथियारों की आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोतों के लिए इस्लामाबाद की खोज के पीछे मुख्य कारक था। पश्चिमी आयुध उत्पादक राष्ट्र और सोवियत संघ सभी अलग–अलग डिग्री में थे, भारत को अलग–थलग करने के डर से पाकिस्तान को हथियार बेचने में संकोच कर रहे थे। इसलिए चीन पाकिस्तान की स्वाभाविक पसंद और हथियारों का पसंदीदा स्रोत बन गया। यह उचित लगा क्योंकि दोनों देशों ने हाल ही में भारत के साथ युद्ध लड़े थे। चीन भी इतना बाधित नहीं था। पश्चिमी शक्तियों की तुलना में उसकी उत्पादन और भंडार क्षमताओं में मामूली कमी होने के बावजूद पाकिस्तान ने उसकी ओर रुख किया या सोवियत संघ पाकिस्तान को 1965 के युद्ध के दौरान या उसके तुरंत बाद, चीनी हथियारों की एक टोकन आपूर्ति प्राप्त हुई, तब से चीन ने एक जारी रखा है पाकिस्तान को हथियारों की आपूर्ति का प्रमुख स्रोत।

प्रमुख संयुक्त उपक्रमः चीन और पाकिस्तान के बीच मौजूदा संयुक्त उपक्रम जून 1990 के समझौता ज्ञापन के प्रावधानों के तहत संचालित होता है जिसे समय–समय पर अद्यतन किया गया है। यह खरीद, अनुसंधान एवं विकास, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सह–उत्पादन में दस साल के सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन था। प्रेसलर संशोधन के तहत पाकिस्तान को सैन्य उपकरणों और प्रौद्योगिकी के मुक्त प्रवाह के अमेरिकी इनकार से फिलिप को भी मिला। रक्षा उत्पादन में कुछ चीन–पाकिस्तानी संयुक्त उद्यम हैंः

अल–खालिद एमबीटी (मुख्य युद्धक टैंक) :–

1 अक्टूबर, 1988 को पाकिस्तान ने चीनी सहायता के साथ एक नए डठज 2000 के निर्माण के लिए औपचारिक रूप से अपनी अल–खालिद परियोजना की घोषणा की थी और जनवरी 1991 में चीन और पाकिस्तान ने संयुक्त रूप से इस टैंक के डिजाइन, विकास और निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। 1991 में प्रदर्शित अल–खालिद के प्रोटोटाइप के बारे में कहा गया था कि इसका निर्माण चीन में किया गया था, भले ही तत्कालीन थल सेनाध्यक्ष जनरल मिर्जा असलम बेग ने दावा किया था कि यह पूरी तरह से पाकिस्तान में निर्मित है। एचआरएफ (तक्षशिला) में पाकिस्तान का विनिर्माण संयंत्र 1992 में पूरा हो गया था और इसे चीन के नोरिन्को उद्योगों के साथ सहयोग करना था, और जब परिचालन में एक वर्ष में लगभग 200 वाहनों के उत्पादन की उम्मीद थी। अल–खालिद परियोजना को 16 जनवरी, 1990 को पाकिस्तान की कैबिनेट की रक्षा समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था और उस वर्ष मई के दौरान चीन और पाकिस्तान के बीच एक औपचारिक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे ।

कारोकोरम – 8 ट्रेनर लड़ाकू :–

यह कामरा में चीन राष्ट्रीय एयरोटेक्नोलॉजी आयात निर्यात निगम और पाकिस्तान एयरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स के बीच एक संयुक्त उद्यम है। इस परियोजना को काराकोरम –8 के रूप में नाम दिया गया था, जब पर्वत श्रृंखला के बाद चीन पाक सीमा का हिस्सा था। यह भी कहा जाता है कि कारोकोरम –8 जेट ट्रेनर ने पाकिस्तान के खुनजेरब –8 कार्यक्रम को ध्वस्त कर दिया। 1990 के दशक की शुरुआत में चीन में तीन प्रोटोटाइप बनाए गए और परीक्षण किए गए और इसके उत्पादन की शुरुआत 1992 के कुछ समय से शुरू होने की उम्मीद थी। लेकिन एमबीटी–अल खालिद की तरह, इसके परीक्षणों ने कुछ बुनियादी समस्याओं को दिखाया है और अब भी यह नहीं है पाकिस्तान की उत्पादन सुविधाओं से बाहर किए जाने की उम्मीद है।

सुपर –7 फाइटर :–

सुपर –7 लड़ाकू के विकास में सहयोग करने वाले चीन–पाकय जो मूल रूप से चाइना एयरोटेक्नोलॉजी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन और अमेरिकी व्याकरण निगम के बीच एक संयुक्त परियोजना थी। तियानमेन स्क्वायर घटना (4 जून, 1989) के बाद वाशिंगटन ीसी ने इस सौदे को बंद कर दिया। 1992 से सुपर –7 को विकसित करने में जूनियर पार्टनर के रूप में पाकिस्तान एयरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स के साथ काम कर रहा है। यहां यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि 1991 में यूएसए द्वारा अपनी साझेदारी के बाद इसे सुपर –7 कहा गया था, जिसका नाम बदलकर फाइटर चाइना– प कर दिया गया था। हालांकि, इस सेनानी के काम में थोड़ी सी भी प्रगति नहीं हुई है।

नौसेना सहयोगय :–

हालांकि जहाज निर्माण में कोई उल्लेखनीय चीन–पाक संयुक्त उद्यम नहीं है, चीन के प्रशिक्षण सुविधाओं में पाकिस्तानी नाविकों को कभी–कभार प्रशिक्षण दिया जाता है। हालांकि चीन की जहाज निर्माण क्षमताओं पर पाकिस्तान की निर्भरता आने वाले वर्षों में बढ़ने की संभावना है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पाकिस्तानी नौसेना ने पारंपरिक रूप से उपकरण और प्रशिक्षण दोनों के लिए पश्चिमी शक्तियों पर भरोसा करना जारी रखा है। फरवरी 1998 में प्रधान मंत्री नवाज शरीफ की चीन यात्रा के दौरान, पाकिस्तानी नौसेना को कथित तौर पर कई चीनी फ्रिगेट्स की पेशकश की गई थी, जो नरम ऋण पर दी गई थी, इस शर्त पर कि उन्हें चीनी और पाकिस्तानी दोनों शिपयार्ड में बनाया जाए। पहले से

ही, पिछले अनुभव के आधार पर, चीन पेट्रोल जहाजों और मिसाइल शिल्प (तालिका देखें) की श्रेणी में प्रमुख आपूर्तिकर्ता रहा है।

चीन से पाकिस्तान की नौसेना खरीद (1970–1991)

क्र.सं.	शस्त्र प्रणालीकानाम	स्थानांतरण का समय	संख्या
1	व्हिस्की श्रेणी की पनडुब्बियां (अनुदान सहायता के रूप में दी गई चीन पनडुब्बिया का पहला निर्यात)	1970	2–3
2	शंघाई– पप श्रेणीः फास्टअटैकक्राफ्ट 4 (मिसाइल बोट में परिवर्तित, वर्तमान में पाकिस्तान की समुद्रीसुरक्षा एजेंसी के साथ 5 को छै द्वारा पुर्जों के लिए रखा गया है)	1972–1976	9
3	हचु आन हाइड्रॉफिल (39 टन)	1974	4–6
4	रोमियो श्रेणी की पनडुब्बियां	1976	2
5	लुडा–क्लासडेस्ट्रॉयर (चीन विध्वं सक का पहला निर्यात)	1976	2
6	हैनेन–क्लास फास्ट अटैक क्राफ्ट गन	1978	3
7	रोमियो श्रेणी की पनडुब्बियां	1980	2
8	हेगू–क्लासः फास्टअटैकक्राफ्टमिसाइल (2 एसवाई–1 मिसाइलों से लैस)	1980–1983	4
9	हुआंगफेन–क्लासः फास्टअटैकक्राफ्टमिसाइल (4 हाईयिंग–2 मिसाइलोंसे लैस)	1984	4
10	शंघाई–11 श्रेणीः फास्टअटैकक्राफ्टगन्स (समुद्री सुरक्षा एजेंसी के साथ)	1986	2
1 1	फ्यूकिंग–क्लास एओआर (।319 ठ पर लिया गया।सवन मजजम पप हेलीकॉप्टर)	1987	1
12	च 58। पेट्रोल क्राफ्ट टाइप करें (राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के साथ)	1990	4
13	टाइप 312 ड्रोनमाइंसवेपर्स (रिमोट कंट्रोल के साथ 5 किलोमीटर तक काम कर सकते हैं)	1991	5

स्रोतः सैन्य संतुलन (लंदनः), पैचतप वर्ष की पुस्तक (स्टॉकहोम), दोनों वर्षों में य ऐनी गिलक और गेराल्ड सेगेल, चीन और आर्म्स ट्रेड (लंदनः क्रूम हेल्म, 1985) और आईडीएसए फाइलें।

हथियार प्रक्रिया :–

चीन–पाकिस्तान रक्षा सहयोग के परिणामस्वरूप एक तरफ एक उन्नत रक्षा उत्पादन क्षेत्र का निर्माण हुआ, जबकि इस संबंध के एक अन्य पहलू ने हथियारों और हथियारों की सीधी खरीद का रास्ता दिया। उनके संयुक्त उद्यमों की तुलना में प्रत्यक्ष हथियार हस्तांतरण अधिक सफल साबित हुए हैं। हथियारों के घरेलू उत्पादन और प्रत्यक्ष खरीद ने नई दिल्ली के साथ सैन्य समानता के लिए पाकिस्तान की लंबे समय से खोज की सुविधा प्रदान की। चीन से पाकिस्तान के हथियारों की खरीद की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि जब अन्य प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं ने संकट के दौरान हथियारों के जखीरे का सहारा लिया, तो 1965 और 1971 में भारत के साथ पाकिस्तान के टकराव के दौरान चीनी सहायता में वृद्धि हुई। इसके अलावा, इन हथियारों को बहुत बार पाकिस्तान को अनुदान के रूप में दिया जाता था, या बहुत कम मित्रता मूल्य पर या कम ब्याज वाले दीर्घकालिक ऋणों के आधार पर दिया जाता है।

अफगानिस्तान संकट और हथियार आपूर्ति :–

अस्सी के दशक में पाकिस्तान ने जिन मामलों को बहुत चिंतित किया है उनमें से एक अफगानिस्तान में सोवियत सैन्य उपस्थिति है। प्रीमियर झाओ ने इस मुद्दे पर पाकिस्तान के रुख का पूरी तरह समर्थन किया। उन्होंने जून को कहा कि चीनी सरकार और लोगों ने इस्लामी शिखर सम्मेलन और संयुक्त राष्ट्र की महासभा के फैसलों का समर्थन किया है कि सोवियत संघ को अफगानिस्तान से हट जाना चाहिए। उन्होंने घोषणा की कि अफगानिस्तान की स्वतंत्रता और गुटनिरपेक्ष स्थिति को बहाल किया जाना चाहिएय अफगानिस्तान के लोगों को अपना भविष्य निर्धारित करने की अनुमति दी जानी चाहिए, और अफगान शरणार्थियों की उनके घरों में वापसी के लिए एक जन्मजात माहौल बनाया जाना चाहिए। चीनी विद्वान एंड्रयू नाथन और रॉबर्ट रॉस, पाकिस्तान और ईरान के साथ अपनी लंबी सीमाओं से निकले चीन के लिए अफगानिस्तान के वास्तविक रणनीतिक महत्व को मानते हैं, दो राज्यों ने चीन को सोवियत विस्तार के खिलाफ बुलंदियों के रूप में महत्व दिया।

सुब्रह्मण्यम को उद्धृत करने के लिए :–

''चीन के लिए खतरा पैदा किए बिना, एक परमाणु पाकिस्तान सोवियत के खिलाफ अपनी रक्षा कर सकेगा।'' चीनी ने कहा कि जैसा कि अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी है, उस देश के 'सोवियत सशस्त्र आक्रमण' ने 'चीन की सुरक्षा' के लिए खतरा पैदा कर दिया। इसके अलावा चीनी को लगा कि सोवियत कदम से उनके दीर्घकालिक सहयोगी पाकिस्तान की सुरक्षा और आंतरिक स्थिरता को खतरा है। 1980–1 तक चीनी और पाकिस्तानी नेताओं के बीच उच्च स्तरीय पारस्परिक दौरे हुए। हर नए पाकिस्तानी और चीनी नेता ने एक दूसरे से संपर्क स्थापित करने को प्राथमिकता दी। इस तरह की यात्राओं ने अक्सर आर्थिक, तकनीकी और रक्षा क्षेत्रों में पाकिस्तान को चीनी सहायता के लिए समझौते किए। मई 1980 में जिया–उल–हक की बीजिंग यात्रा ने अफगानिस्तान संकट पर विचारों की एकमत का निर्माण किया। चीन के प्रमुख हुआ गुओ–फेंग ने सोवियत संघ को 'दक्षिण एशियाई देशों की सुरक्षा के लिए खतरा' और 'एशिया और पूरे विश्व की शांति' के लिए एक गंभीर खतरा बताया। सितंबर 1980 में प्रधान मंत्री बने चीन के प्रधानमंत्री झाओ जियांग ने क्षेत्रीय सुरक्षा और राजनीतिक मामलों पर परामर्श के लिए मई जून 1981 में पाकिस्तान की अपनी पहली यात्रा की।

संदर्भ

पाकिस्तान, चीन को आगे डीप स्ट्रेटेजिक टाईज संख्या 1।

क्यू एंड ए चीन–पाकिस्तान मुक्त व्यापार समझौते पर चोंग क्वान द्वारा, वाणिज्य मंत्रालय के प्रवक्ता श, 27 नवंबर, 2006, सं। 18. फजल–उर–रहमान, संख्या 3, पृ– 54।

सैयद फजल–ए–हैदर, पदह पाकिस्तान में चीन का बढ़ता कदम ', एशिया टाइम्स ऑनलाइन, 30 नवंबर, 2006, इशरत हुसैन, सं। 19, पृ– 7।

महमूद–उल–हसन खान, पहीजे पाक–चीन संबंधों की नई ऊंचाई श, 5 मार्च, 2006 को फजल–उर–रहमान में उद्धृत किया गया, संख्या 3, पृष्ठ 58।

मुक्त व्यापार समझौते पर चीनी व्यवहार्यता अध्ययन, फजल–उर–रहमान में उद्धृत, संख्या 3, पृष्ठ 64।

मांगी, प पाकिस्तान नेशनल बैंक सीकिंग चाइना वेंचर पार्टनर ', इंटरनेशनल हेराल्ड ट्रिब्यून, 18 अप्रैल, 2007, चीन पर संक्षिप्त, निवेश बोर्ड, पाकिस्तान सरकार, सं– 25

पाकिस्तान, चीन को आगे डीप स्ट्रेटेजिक टाईज श, संख्या 1. फजल–उर–रहमान, संख्या 3, पृष्ठ 66।

पाकिस्तान, चीन को आगे डीप स्ट्रेटेजिक टाईज श, संख्या 1।

पाकिस्तान चीनी निवेश का स्वागत करता हैरू पी एम, पाकिस्तान का एसोसिएटेड प्रेस, सैयद फजल–ए–हैदर, 'चीनी आई पाकिस्तान का रियल एस्टेट', एशिया टाइम्स ऑनलाइन, 17 जनवरी, 2007,।

समाचार, 22 फरवरी, 2006, फजल–उर–रहमान में उद्धृत किया गया, संख्या 3, पृष्ठ 67।

फजल–उर–रहमान, संख्या 3, पृष्ठ 59।

जॉन डब्ल्यू गवर, सेंट्रल, साउथ–वेस्ट और साउथ एशिया के साथ चीन के ओवरलैंड ट्रांसपोर्टेशन लिंक का विकास ', द चाइना क्वार्टरली, 185, मार्च 2006, पृष्ठ 1–2।

साईबाल दासगुप्ता, पाक बेंड ओवर ओवर बीजिंग, ऑफर ऑयल बैकअप ', द टाइम्स ऑफ इंडिया, 20 मार्च, 2007।

मुहम्मद इफ्तिखार राजा, काराकोरम हाइवे–द फ्रेंडशिप ब्रिज अक्रॉस द हिमालय ', बीजिंग रिव्यू, 8 जून, 2006, पृष्ठ 7।

डॉन, 5 जुलाई 2006, पब्लिक ओपिनियन ट्रेंड्स पाकिस्तान, 34 (156), 6 जुलाई 2006, पृष्ठ 2 में उद्धृत किया गया।

ग्वादर में निवेश करने के लिए चीन इतना उत्सुक क्यों है? 'पाकिस्तान और खाड़ी अर्थशास्त्री, 29 मई – 4 जून, 2006, पृष्ठ 56।

डॉन, 20 फरवरी, 2007, पब्लिक ओपिनियन ट्रेंड्स पाकिस्तान, 35 (43), 21 फरवरी, 2007, पृष्ठ 40 में उद्धृत किया गया।

डेविड मोंटेरो,, चीन, पाकिस्तान टीम एनर्जी अप ', द क्रिश्चियन साइंस मॉनिटर, 13 अप्रैल, 2007,

21 फरवरी 2006 को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के बीच संयुक्त बयान का पाठ

पाकिस्तान–चीन एनर्जी फोरम हेल्ड इन इस्लामाबाद श, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के विदेश मामलों का मंत्रालय, 3 मई, 2006, 25 नवंबर, 2006 को पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के बीच संयुक्त वक्तव्य निरुपमा सुब्रमण्यन,, चीन, पाकिस्तान इंक मुक्त व्यापार समझौता द हिंदू, 25 नवंबर, 2006।

पाकिस्तान, चीन को आगे डीप स्ट्रेटेजिक टाईज, संख्या 1।

राजदूत (सेवानिवृत्त) इशरत अजीज, ंदक गल्फ ऑयल एंड इंडियाज एनर्जी नीड्स ', भारत स्ट्रेटेजिक, 1 फरवरी, 2006, पृष्ठ 47–48।

नंदकुमार जे, भारत, चीन और ऊर्जा सुरक्षा एशिया टाइम्स, 7 फरवरी, 2004

स्टीव ए यतिव और चुनलॉन्ग लू, ल्मज चाइना, ग्लोबल एनर्जी एंड द मिडल ईस्ट श, मिडिल ईस्ट जर्नल, 61 (2), 2007, पृष्ठ 199।

शमीम अहमद रिजवी, ंद क्या पाकिस्तान एक ऊर्जा संपन्न देश है? , पाकिस्तान और गल्फ इकोनॉमिस्ट, जुलाई 3–9, 2006, , पृष्ठ 19।